Seventeenth Loksabha

>

Title : Request to provides at least 200 days of job to below poverty line card holders in Madhya Pradesh and construct toilet with Pradhan Mantri Awas Housing .

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं शून्य काल में जो विषय बोलने जा रहा हूँ, हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हुए हैं । अगर किसी ने गरीबों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कोशिश की है तो वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी हैं । उनको रहने के लिए घर, घर में बिजली, उज्जवला गैस, नल से जल और पक्का मकान दिया गया है । ये सब काम अगर कोई करवा रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो छोटी-छोटी बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । हमारे देश के जनजातीय क्षेत्र में, विशेषकर जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, जिसमें सेलाना, थांडला, पेटला, झाबुआ, जोर्बट और अलीराजपुर हैं, यह पूरा जनजातीय क्षेत्र है । यहाँ पर करीब-करीब 70 से 80 प्रतिशत लोग या तो खेती करते हैं, या खेत में मजदूरी करते हैं । हमारे मध्यप्रदेश में जॉब कार्ड पर एक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है और एक दिन की मजदूरी 192 रुपये दी जा रही है । चूंकि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिले में जो परिवार हैं, वह करीब औसत 10 लोगों का परिवार होता है और एक आदमी को साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है । इससे उसके परिवार के पालन-पोषण में थोड़ी दिक्कत आती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो भूमिहीन किसान हैं, उनको साल में कम से कम 200 दिन का

रोजगार दिया जाए । हमारे जो पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, उन राज्यों में जो मजदूरी दी जा रही है, वह मजदूरी भी मध्यप्रदेश में दी जाए, जो कि लगभग 300 रुपये प्रतिदिन होती है ।

दूसरा, हमारे मध्यप्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें शौचालय बनाने की अनिवार्यता नहीं है । पहले समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ शौचालय बन गए, परंतु जो नए प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें स्थान चेंज हो रहा है । स्थान चेंज होने के कारण, पूर्व में जिनको शौचालय स्वीकृत हो गया था, उनको प्रधानमंत्री आवास के साथ शौचालय नहीं दिया जा रहा है । उसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के झाबुआ जिले में, जो कि वर्ष 2018 में ओ.डी.एफ. घोषित हो गया है, अब लगभग 25 से 30 प्रतिशत आबादी खुले में शौच के लिए जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के साथ शौचालय का अनिवार्य निर्माण हो ।